



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1936 (श10)
(सं0 पटना 362) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2015

सं0 08/आरोप-01-23/2014,सां0प्र0-1573

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जनवरी 2015

श्री राधा बिहारी ओझा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक-28/08, तत्कालीन बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध श्री शिवजी प्रसाद वर्मा, मोहररि बन्दोवस्त कार्यालय, दरभंगा को विभागीय कार्यवाही के उपरांत उन्हें अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में श्री ओझा द्वारा विलम्ब से दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड संसूचित करने के साथ उन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन देने का आदेश पारित करने संबंधी आरोप के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1424, दिनांक 26.09.2011 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' के आधार पर श्री ओझा से पत्रांक-13127, दिनांक 02.12.2011 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री ओझा ने अपने स्पष्टीकरण में मूल रूप में अंकित किया की श्री वर्मा के मामले में निर्णय लेने में जो विलम्ब हुआ उसके स्पष्ट कारण थे। संचिका के उपस्थापन, पृच्छा के उत्तर एवं विमर्श में संचिका लंबित हुई। श्री वर्मा को जो भी दंड उनके द्वारा अधिरोपित की गयी वह उन्होंने उत्तम विवेक से दिया था। वे अनुशासनिक प्राधिकार थे और इसके लिए वे सक्षम थे।

श्री ओझा से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री ओझा द्वारा श्री वर्मा को दिये गये शास्ति को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ने अपर्याप्त बताया गया एवं श्री वर्मा के मामले में पुनः आदेश पारित करने का आदेश दिया। श्री ओझा के प्रतिस्थानी बन्दोवस्त पदाधिकारी ने श्री वर्मा के मामले में संशोधित आदेश

पारित किया जिसमें दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा यथावत रखी, परन्तु निलंबन अवधि के लिए निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा का आदेश पारित किया गया।

श्री ओझा दिनांक 31.07.2011 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं उक्त कदाचार को गंभीर कदाचार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता फलस्वरूप श्री शर्मा के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तद्आलोक में सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विषयगत मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 362-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>